वासी क्षेत्रों में और अधिक डाकघर खोलने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अद्यतन आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

(i) मध्य प्रदेश में ग्रामों की संख्या 71,352

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या 9,521

(ख) जी हां।

(ग) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 230 नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इनमें पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लिए 148 डाकघर भी शामिल हैं।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रबन्ध-निदेशक का रिक्त पद

1962. श्री अजीत जोगी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के, जिसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, प्रबंध निदेशक का पद लम्बे अरसे से रिक्त है ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बात को मद्देनजर रखते हुये कि ऐसे महत्वपूर्ण पद के न भरे जाने का कम्पनी की दक्षता तथा उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यह पद कब तक भर दिया जायेगा?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां। यह पद 15-7-1988 से रिक्त है।

(ख) यह पद समय पर इसलिये नहीं भरा जा सका क्योंकि उक्त पद पर नियुक्ति के लिये बनाया गया पैनल (सूची) में दूसरे स्थान के व्यक्ति के विरुद्ध एक आपराधिक मामला लंबित था। संबद्ध अधिकारी ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपना फैसला समय पर नहीं दिया। उच्च न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला 2-9-1988 को दिया जिसमें संबंधित अधिकारी को सभी आरोपों से दोष-मुक्त कर दिया। इस बीच, उक्त पैनल (सूची), जो 27-8-1988 तक ही मान्य था, की विधि समाप्त हो गयी। इसलिये उक्त पैनल (सूची) को पुनर्मान्य कराने के लिये पी० ई० एस० बी० से संपर्क किया जाना आवश्यक हो गया जो कि अब 31-12-1988 तक के लिये पुनर्मान्य हो गया है।

(ग) शीर्षस्थ रिक्त पदों पर नियुक्ति न किये जाने से संगठन की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस मामले में विभाग के उपयुक्त वर्णित अपरिहार्य कारणों के कारण रिक्त पद को भरना संभव नहीं हो पाया। इस संबंध में रिक्त पद को शीघ्र भरने के लिये कदम उठाये गये हैं।

मध्य प्रदेश के पहाड़ी तथा पिछड़े इलाकों में टेलीफोन सुविधाएं

1963. श्री अजीत जोगी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन पहाड़ी तथा पिछड़े इलाकों के नाम क्या हैं, जिनमें चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन सुविधा दे दिये जाने की संभावना है और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति की गई है ; और

(ख) क्या चालू पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के सभी जन-जातीय क्षेत्रों के विकास खंड मुख्यालयों को टेलीफोन सुविधा दे दिये जाने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) मध्य प्रदेश के पूर्णतया/आंशिक रूप से पिछड़े 34 जिलों में 5–5 कि०मी० की भुजा के 517 आबादी वाले षटभुजाकार क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है । इनमें से 325 षटभुजाकार क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधायें पहले प्रदान कर दी गई हैं ।

(ख) सभी जनजातीय ब्लाक मुख्यालयों में दूरसंचार सुविधायें प्रदान कर दी गई हैं ।

Soviet aid to Power Sector

1964. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Soviet Union has offered to provide more aid for power sector in India; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALP-NATH RAI): (a) and (b) An Inter-Governmental Protocol has recently been signed with the Government of USSR for construction, upto 2000 A.D., of new electric power stations with a total capacity upto 6000 MW, along with the associated transmission systems, with Soviet Assistance. Under the Protocol five power projects, with a total capacity of 3270 MW are to be constructed and synchronised *y* during the Eighth Five Year Plan. A credit Agreement, providing financial assistance of Roubles 400 million for Vindhya-chal Super Thermal Power Project Stage-II, has also been concluded with the Government of USSR.

कानपुर में असंतोषजनक टेलीफोन सेवा

1965. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युवा उद्योग व्यापार मंडल, कानपुर के आह्वान पर कानपुर टेलीफोन्स की कुव्यवस्था के विरोध में 26 सितम्बर, 1988 को टेलीफोन की शव यात्रा निकाली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां, कानपुर में असंतोषजनक टेलीफोन सेवाओं के विरोध में 26 सितम्बर, 1988 को टेलीफोन की शवयात्रा निकाली गई थी ।

(ख) आन्दोलनकारियों से विचार विमर्श करके और एक्सचेंजों में उत्पन्न दोषों की व्यापक जांच करके उन्हें दूर करने जैसे सुधारात्मक कदम उठा कर इस मामले को सुलझा दिया गया था ।

Visit of Deputy Director General of World Intellectual Property Organisation to India

1966. SHRI SHAMIM HASHMI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) how many times Mr. Shahid Ali Khan, Deputy Director General of World Intellectual Property Organisation (WIPO) has visited India during the last six months;

(b) whether it is a fact that he has held discussions with the Senior Officials of the Ministry persuading India to join the Pans Convention; and